राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकलपीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 529/2023

1. खेड़ाराम पुत्र भगवाना राम, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी मगापा की ढाणी, जेरन मार्ग, जुजानी थाना भीनमाल, जालोर (राजस्थान)। (उप जेल, भीनमाल में कैद)।

2. श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री खेड़ा राम, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी मगापा की ढाणी, जेरन मार्ग, जुजानी थाना भीनमाल, जालोर (राजस्थान)। (उप जेल, भीनमाल में कैद)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार पीपी के माध्यम से।

2. भीमा राम पुत्र रेखा राम, निवासी गांव नवा पुरा भीनमाल, जिला जालौर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिककर्ता (गण) की ओर से	:	श्री धीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगदीशसिंह द्वारा सहायता प्रदान की गई।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री अनिल जोशी, जीए-सह-एएजी श्री प्रवीण व्यास के स्थान पर श्री विनीत जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति फरजंद अली

आदेश

आदेश सुरक्षित करने की तारीख : 04.07.2023

आदेश उच्चारित करने की तारीख : 07.07.2023

रिपोर्टेबल

न्यायालय द्वारा:-

1. सीआरपीसी की धारा 167 (2) के अंतर्गत याचिकाकर्तागण द्वारा अपर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल के समक्ष डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन किया गया था, जिसे 27.03.2023 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया था।

2. 27.03.2023 के आदेश से व्यथित, याचिकाकर्तागण ने अपर सत्र न्यायाधीश, भीनमाल के समक्ष सीआरपीसी की धारा 167 (2) के अंतर्गत एक और आवेदन दायर किया, जिसे 03.05.2023 के आदेश के अंतर्गत इस कारण से निपटा दिया गया कि धारा 167 का दायरा समाप्त हो गया था और इस प्रकार, याचिकाकर्तागण द्वारा दायर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए प्रार्थना करने वाला आवेदन अपना आधार खो चुका था; यह भी टिप्पणी की गई थी कि आरोप-पत्र दायर करने की तारीख से संज्ञान लेने की तारीख तक आवेदकों की हिरासत की वैधता के प्रश्न पर निर्णय करना उच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र था।

3. 03.05.2023 के आदेश से असंतुष्ट, याचिकाकर्तागण द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।

4. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया था, जहां आरोप-पत्र दायर करने के काफी समय बीत जाने के बावजूद संज्ञान का आदेश पारित नहीं किया गया था और एक अन्य आरोपी के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए धारा 190 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन के संदर्भ में कई स्थगनों के कारण मामले को लंबित रखा गया था। आरोप-पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण को वैधानिक जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किए बिना विस्तारित अवधि के लिए हिरासत में भेज दिया गया था और अंततः, डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाले उनके आवेदन को 27.03.2023 के आदेश के तहत अपास्त कर दिया गया था। आरोप-पत्र दायर करने के बाद और संज्ञान लेने से पहले याचिकाकर्तागण की हिरासत

की अवधि का विस्तार अनुचित और अवैध था।

5. उन्होंने आगे कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट को 90 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान लेना चाहिए था और जैसाकि वह ऐसा करने में विफल रहे, धारा 167 सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत का अधिकार याचिकाकर्तागण के पक्ष में स्वचालित रूप से अर्जित हो जाता है। याचिकाकर्तागण को न्यायिक रिमांड का विरोध करने का कोई अवसर नहीं दिया गया क्योंकि वे न्यायालय में मौजूद नहीं थे, इस प्रकार, इस मामले में भी धारा 167 के जनादेश का उल्लंघन किया गया था।

6. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भीनमाल द्वारा पारित 03.05.2023 के आदेश को इस हद तक अपास्त करने के लिए प्रार्थना की कि यदि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित जमानत बांड भरने के इच्छुक हैं, तो विद्वान मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायाधीश को याचिकाकर्तागण को वैधानिक जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

7. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों के विपरीत, जीए-सह-एएजी याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थना का विरोध करता है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। आक्षेपित आदेशों का अवलोकन किया गया।

9. प्रारंभ में, यह उल्लेख करना उचित होगा कि डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए कानून की आवश्यकता केवल जांच पूरी करने और आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के लिए है और माना जाता है कि इस मामले में, एजेंसी ने 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर किया था, इसलिए, डिफ़ॉल्ट जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भीनमाल द्वारा यह सही कहा गया है कि एक बार निर्धारित समय के भीतर आरोप-पत्र दायर करने के बाद, डिफ़ॉल्ट जमानत की कोई गुंजाइश

नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संज्ञान लिया गया है या नहीं, जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य(2013) 3 एससीसी 77 में प्रकाशित*** मामले में भी कहा गया है।

10. यदि एजेंसी इस प्रावधान के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर करने में विफल रहती है, तो आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार है। इस प्रश्न का कि क्या सीआरपीसी की धारा 167 काम करेगी यदि आरोप-पत्र दायर किया गया है, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में पर्याप्त रूप से उत्तर दिया गया है। **संजय दत्त बनाम राज्य** (1994) 5 एससीसी 410 में प्रकाशित मेंमाननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि सीआरपीसी की धारा 167 के तहत प्रदान की गई वैधानिक जमानत का आरोपी का अधिकार केवल तब तक मौजूद है जब तक कि आरोप-पत्र दायर नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि जब जांच एजेंसी निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर करने में चूक करती है। यदि अभियुक्त सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमानत की मांग करता है जब चूक की गई है और उस समय तक आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है, तो वह डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के योग्य हो जाता है, यदि अभियुक्त जमानत मांगता है, भले ही चूक की गई हो, लेकिन आरोप-पत्र अंततः उस समय तक दायर किया गया था। वह डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के योग्य नहीं होता और उसकी जमानत याचिका पर गुणागुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा जैसे कि किसी भी नियमित जमानत आवेदन पर जमानत देने वाले सिद्धांतों के अनुसार निर्णय किया जाता है।

11. इस पहलू पर सबसे हालिया निर्णयों में से एक ***गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम राहुल मोदी और अन्य*** में दिया गया था। एआईआर 2022 एससी 902 में प्रकाशित जिसमें ***भीकमचंद जैन*** (सुप्रा.) में

निर्धारित अनुपात का उल्लेख किया गया था और यह माना गया था कि आरोप-पत्र दायर करना सीआरपीसी की धारा 167 का पर्याप्त अनुपालन है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर किया गया है तो आरोपी के पक्ष में वैधानिक जमानत का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जांच करने के बाद और भले ही संज्ञान नहीं लिया गया हो, आरोपी को गुणागुण के आधार पर नियमित जमानत के लिए अदालत जाने का अधिकार है।**धारा 167 के तहत परिकल्पित वैधानिक जमानत के अधिकार का संचालन जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट दायर होने के बाद समाप्त हो जाता है क्योंकि इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि आरोपी हिरासत में है तो जांच एक निश्चित और उचित अवधि के भीतर पूरी हो जाए।** चूंकि आपराधिक प्रक्रिया में जांच और संज्ञान लेना दो अलग-अलग चरण हैं और बाद में शुरू होता है जब पहला चरण पूरा हो जाता है, इसलिए किसी भी मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत के आवेदन का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि संज्ञान लिया गया है या नहीं।

12. डिफ़ॉल्ट जमानत के विषय पर कानून बहुत स्पष्ट है और ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है जिसमें याचिकाकर्तागण को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत रिहा किया जा सके क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप-पत्र दायर किया गया था। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत आरोपी को रिहा करने की प्रार्थना किसी भी विधिक आधार के बिना है और इसलिए, इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

13. एक बार 90 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर 17.01.2023 को आरोप-पत्र दायर होने के बाद, धारा 167 सीआरपीसी के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत की गुंजाइश समाप्त हो गई, लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया, इसलिए पोस्ट-संज्ञान चरण शुरू नहीं हुआ जहां सीआरपीसी के अन्य प्रावधान काम कर सकते थे और जब 28.04.2023 को आखिरकार

संज्ञान लिया गया, लगभग 100 दिनों की अवधि बीत चुकी थी। इस विसंगतिपूर्ण स्थिति ने इस न्यायालय को कानून के प्रश्न पर विचार करने और विस्तृत करने के लिए प्रेरित किया, जैसाकि अगले पैराग्राफ में विचार-विमर्श किया गया है।

14. निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर करने के बाद और मामले की स्थापना से पहले या इस मामले में सामने आए मामले को अंजाम देने या प्रतिबद्ध करने के लिए कार्यवाही करने से पहले और विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने जो कुछ हुआ उस पर ध्यान देने और उसके द्वारा पारित आदेश पर नाराजगी महसूस करने के बाद आरोपी को हिरासत की वैधता से संबंधित प्रश्न पर विचार करना, 16.05.2023 के आदेश के माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आरोपी को हिरासत की अवधि के लिए मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जो उसने बिताया था यदि इस तरह की हिरासत कानून के बल के बिना पाई जाती है।

15. अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने कुछ गलतफहमी के तहत उत्तर दिया था और यह समझाने का प्रयास किया था कि उन्हें धारा 167 सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्तागण की रिमांड की अवधि क्यों बढ़ानी पड़ी। इस बिंदु पर कानून बहुत स्पष्ट है जैसाकि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है और सीआरपीसी की धारा 167 में निर्धारित डिफ़ॉल्ट जमानत के दायरे के संबंध में उत्तर देने के लिए कोई प्रश्न नहीं बचा है और आगामी खंड में धारा 167 सीआरपीसी के तहत रिमांड के दायरे पर चर्चा की गई है।

16. अपने हित के प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले विद्वान मजिस्ट्रेट से फिर से स्पष्टीकरण मांगने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि अधिकारी को अपनी बात कहने और अपने दृष्टिकोण/परिप्रेक्ष्य को समझाने का अवसर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, ***अश्विनी विजय शिरियानवर बनाम कर्णाटक राज्य और अन्य*** (2023 की आपराधिक अपील संख्या

1616) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ द्वारा हाल ही में पारित एक निर्णय पर विचार करते हुए दिनांक 19.05.2023 के आदेश के तहत, जिसमें यह राय दी गई थी कि एक चूककर्ता अधिकारी के खिलाफ कोई टिप्पणी करने या कोई निर्देश पारित करने का आदेश उस अधिकारी को अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता है, जिसका करियर और सम्मान इससे प्रभावित होगा, इस न्यायालय का विचार था कि उसके खिलाफ आदेश पारित करने से पहले विद्वान मजिस्ट्रेट के विचारों को जानना उचित है, इस प्रकार, दिनांक 23.05.2023 के एक विस्तृत आदेश के माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट से एक और स्पष्टीकरण मांगा गया था।

17. अब, इस अदालत को 23.05.2023 के आदेश के अनुपालन में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत हलफनामा प्राप्त हो चुका है। अधिकारी ने उनसे पूछे गए प्रश्नों का बिंदुवार तरीके से उत्तर दिया है। सबसे पहले, उन्होंने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है कि क्या संज्ञान लिया गया था और 90 दिनों की समाप्ति के बाद मामला स्थापित नहीं किया गया था और उन्होंने रिमांड के विस्तार का आदेश पारित किया था। उन्होंने यह भी कहा है कि 90 दिनों की समाप्ति के तुरंत बाद संज्ञान नहीं लिया गया था। दूसरा, उन्होंने समझाया है कि रिमांड का आदेश सीआरपीसी की धारा 209 के तहत पारित किया गया था। तीसरा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई है जिसे "आंशिक आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद संज्ञान नहीं लेना" कहा जाता है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पास अपराध का तुरंत संज्ञान लेने और फिर, धारा 190 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को स्थगित करने का एक और विकल्प था, क्योंकि अपराध का संज्ञान लिया जाता है और अपराधी का नहीं, लेकिन **सुनीता देवीऔर अन्य बनामबिहार और अन्य राज्य** (2008 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 937) में पारित निर्णय का उल्लेख किया है। अंत में, हलफनामे से यह स्पष्ट होता है कि

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के लिए बिना शर्त माफी मांगी गई है।

18. इस समय, रिमांड के विषय पर कानून की स्थिति को स्पष्ट करना उचित समझा जाता है। इस मामले में जो प्रश्न उभर रहा है वह गोधूलि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए, इस पर स्पष्टीकरण देना उचित है।

19. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार रिमांड का आदेश केवल तीन स्थितियों/शर्तों में पारित किया जा सकता है और इन तीन शर्तों को छोड़कर, रिमांड की अवधि को आगे बढ़ाने या बढ़ाने के लिए संहिता के किसी अन्य प्रावधान में कोई विकल्प निर्धारित नहीं है। इन तीन शर्तों को निम्नलिखित तीन प्रावधानों में शामिल किया गया है:

क) सीआरपीसी की धारा 167

ख) सीआरपीसी की धारा 209

ग) सीआरपीसी की धारा 309

क) धारा 167 सीआरपीसी: प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती है।

20. सीआरपीसी की धारा 167 इस संबंध में रिमांड देने को नियंत्रित करती है और इसे आसान संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **167. ऐसी प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती हो**- 1) जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 57 द्वारा निर्धारित चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती है, और यह मानने के आधार हैं कि आरोप या जानकारी सुस्थापित है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी, यदि वह उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, तो मामले से संबंधित

निर्धारित डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को तुरंत प्रेषित करेगा, और उसी समय अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे इस धारा के तहत किसी अभियुक्त व्यक्ति को अग्रेषित किया जाता है, समय-समय पर, चाहे उसके पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र हो या न हो, समय-समय पर अभियुक्त को ऐसी हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है, जैसाकि ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझता है, कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए; और यदि उसके पास मामले की सुनवाई करने या इसे परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और आगे की हिरासत को अनावश्यक मानता है, तो वह आरोपी को ऐसे अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने का आदेश दे सकता है:

बशर्ते कि-

(क) मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को पंद्रह दिनों की अवधि से परे, पुलिस की हिरासत के अलावा, अन्यथा हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस पैराग्राफ के तहत अभियुक्त व्यक्ति को हिरासत में कुल अवधि से अधिक के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

(i) नब्बे दिन, जहां जांच मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय अपराध से संबंधित है;

(ii) साठ दिन, जहां जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है, और, नब्बे दिनों या साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर,

जैसा भी मामला हो, आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है, और इस उप-धारा के तहत जमानत पर रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति को उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत रिहा माना जाएगा;

(ख) कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत पुलिस की हिरासत में अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत नहीं करेगा, जब तक कि अभियुक्त को पहली बार व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है और बाद में हर बार जब तक कि आरोपी पुलिस की हिरासत में रहता है, लेकिन मजिस्ट्रेट आरोपी को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से प्रस्तुत करने पर न्यायिक हिरासत में और अधिक हिरासत बढ़ा सकता है;

ग) द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त नहीं है, पुलिस की हिरासत में हिरासत को अधिकृत नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण I.- संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि, पैराग्राफ (क) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बावजूद, अभियुक्त को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत प्रस्तुत नहीं करता है।

स्पष्टीकरण II.- यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति को खंड(ख) के तहत आवश्यक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो आरोपी व्यक्ति की पेशी को हिरासत को अधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से आरोपी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के बारे

में सिद्ध किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला के मामले में, हिरासत रिमांड होम या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थान की हिरासत में रहने के लिए अधिकृत होगी।

(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि वह उप-निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं है, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर सकता है, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, मामले से संबंधित इसके बाद निर्धारित डायरी में प्रविष्टि की एक प्रति, और उसी समय, अभियुक्त को ऐसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा, और उसके बाद, ऐसा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अभियुक्त व्यक्ति को ऐसी हिरासत में हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है जो वह कुल मिलाकर सात दिनों से अधिक की अवधि के लिए उपयुक्त समझे; और इस तरह से अधिकृत हिरासत की अवधि की समाप्ति पर, आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, सिवाय इसके कि आरोपी व्यक्ति को आगे हिरासत में रखने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है।

परन्तु उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले, कार्यकारी मजिस्ट्रेट मामले से संबंधित डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति के साथ मामले के रिकॉर्ड निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा, जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा उसे प्रेषित किया गया था, जैसा भी

मामला हो।

(3) इस धारा के तहत पुलिस की हिरासत में हिरासत को अधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा।

(4) ऐसा आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट अपने आदेश की एक प्रति, इसे बनाने के कारणों के साथ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(5) यदि किसी मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामले के रूप में सुनवाई की जाती है, तो आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, तो मजिस्ट्रेट अपराध की आगे की जांच को रोकने का आदेश देगा जब तक कि जांच करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट को संतुष्ट नहीं करता कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में छह माह की अवधि के बाद जांच जारी रखना आवश्यक है।

(6) जहां उपधारा (5) के तहत किसी अपराध की आगे की जांच को रोकने का कोई आदेश दिया गया है, तो सत्र न्यायाधीश, यदि वह संतुष्ट है, तो उसे या अन्यथा, उसे किए गए आवेदन पर कि अपराध की आगे की जांच की जानी चाहिए, उप-धारा (5) के तहत किए गए आदेश को खाली कर सकता है और जमानत और अन्य मामलों के संबंध में ऐसे निर्देशों के अधीन अपराध में आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है, जैसाकि वह निर्दिष्ट कर सकता है।

21. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट, जिसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी (उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं) द्वारा इस प्रावधान के तहत आरोपी को अग्रेषित किया जाता है, यह मानने का आधार है कि आरोप/खुफिया

जानकारी सुस्थापित है, आरोपी को पुलिस हिरासत/न्यायिक हिरासत में 15 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है; बशर्ते कि मजिस्ट्रेट पंद्रह दिनों की अवधि से परे पुलिस की हिरासत के बजाय अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। मजिस्ट्रेट इस तरह की हिरासत को 15 दिनों के छोटे टुकड़ों में कुल 90 दिनों तक अधिकृत कर सकता है, जहां मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध की जांच की जा रही है और कुल 60 दिनों तक जहां किसी अन्य अपराध की जांच की जा रही है, लेकिन हिरासत एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर बार उसकी रिमांड बढ़ाए जाने पर उसे प्रस्तुत करना होता है। 90 या 60 दिनों की समाप्ति के बाद, जैसा भी मामला हो, यदि जांच पूरी नहीं हुई है और आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है, तो आरोपी को केवल इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसे आम बोलचाल में वैधानिक जमानत कहा जाता है।

22. वर्तमान मामले में भी, 90 दिनों की निर्धारित अवधि से परे सीआरपीसी की धारा 167 के तहत रिमांड का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस धारा के तहत रिमांड को आगे बढ़ाने का अधिकार 90 दिनों की अवधि की अंतिम तारीख को समाप्त हो गया।

न्यायिक कार्यवाही की शुरुआत:

23. जब जांच एजेंसी का कार्य समाप्त हो जाता है, तो न्यायपालिका का कार्य शुरू होता है; जांच की समाप्ति या जांच की अंतिम तारीख तब होती है जब सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट अग्रेषित की जाती है और न्यायिक कार्य पहली तारीख को शुरू होता है जब फाइल न्यायिक हाथों में चली जाती है। सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा जांच पूरी होने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट अग्रेषित करने के चरण को धारा

190 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है, जब यह न्यायिक हाथों में पहुंच गया है और यदि मामला औपचारिक रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाता है, तो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान के रूप में कहा जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त रिपोर्ट प्राप्त करना **न्यायिक कार्यवाही शुरू करने का प्रवेश द्वार है।**

24. यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91, 156, 157, 164, 169 और 170 में निहित प्रावधानों से अवगत है, लेकिन इस न्यायालय की राय है कि संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत परिकल्पित कार्यवाही में मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। एक वास्तविक न्यायिक कार्य करना। मजिस्ट्रेट धारा 173 के तहत पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मुकदमे की प्रक्रिया में पहला वास्तविक न्यायिक कदम उठाता है। इन विशिष्ट प्रावधानों को संहिता में केवल जांच एजेंसियों जैसे आपराधिक न्याय प्रणाली के हितधारकों के कार्य पर पर्यवेक्षी नजर रखने और इन प्रावधानों में निर्धारित कृत्यों पर वैधता की प्रभावी भावना प्रदान करने की दृष्टि से स्थान दिया गया था और यह सिर्फ एक न्यायिक जांच है ताकि एजेंसी की विकृतियों को रोका जा सके। कानून के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर अंकुश लगाएं और जांच कार्य में सहायता प्रदान करें। मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच के चरण के दौरान पर्दे के पीछे एक भूमिका निभाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्पक्ष खेल हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यही कारण है कि आपराधिक मामले की यात्रा में इस चरण के लिए 'गेटवे' शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया अपने सही अर्थों में तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि एक आपराधिक मामले की फाइल चेक-पॉइंट से गुजर न जाए, जिन्हें संज्ञान लेने के चरण से पहले चतुराई से तैयार किया गया है।

25. सीआरपीसी की धारा 91 अदालत को किसी भी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करने का अधिकार देती है जो इस संहिता के तहत किसी भी जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय है। मजिस्ट्रेट इस प्रावधान के तहत कुछ दस्तावेजों को तलब करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यह केवल उस व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा कोई दस्तावेज या चीज माना जाता है, क्योंकि इस तरह के समन में आधिकारिक अधिकार होता है और मामले में आगे बढ़ने के लिए न्यायिक दिमाग का कोई प्रयोग शामिल नहीं होता है। धारा 91 के तहत समन जारी करने की जो शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है, वह किसी भी अधिकारी के पास है जो एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, जिससे इस सिद्धांत को मजबूत किया जा सकता है कि इस प्रावधान के तहत मजिस्ट्रेट का कार्य ऐसा नहीं है जिसमें आगे बढ़ने के लिए दिमाग का प्रयोग शामिल है।

26. सीआरपीसी की धारा 156 में प्रावधान है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे धारा 190 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है, वह इस प्रावधान में उल्लिखित किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच का आदेश दे सकता है और धारा 91 के समान, एक पुलिस स्टेशन प्रभारी को समान शक्ति प्रदान की गई है।

27. सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका इस बिंदु तक भी सीमित है कि एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी तुरंत ऐसे मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसे मामले में संज्ञान लेने का अधिकार है यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि एक संज्ञेय अपराध (जिसे वह धारा 156 के तहत जांच करने का अधिकार प्राप्त है) किया गया है। यह प्रावधान सिर्फ समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है ताकि पुलिस या कोई अन्य जांच एजेंसी कोई अनुचित हस्तक्षेप न कर सके और एफआईआर के सही समय के साथ-साथ आरोप की प्रकृति, आरोपी का

नाम, घटना का स्थान आदि के संबंध में उपयोग किए गए शब्द अपरिवर्तित रहें। यह मिलावट के लिए कोई दरार नहीं छोड़ता है और यहां, मजिस्ट्रेट का ऐसा कुछ भी नहीं है।

28. सीआरपीसी की धारा 164 की विषय-वस्तु पर आते हुए, इस प्रावधान को पढ़ने से समझा जा सकता है कि एक मजिस्ट्रेट जांच के दौरान या जांच या परीक्षण शुरू होने से पहले किसी भी समय उसके सामने किए गए किसी भी कबूलनामे या बयान को रिकॉर्ड कर सकता है। शब्द '... जांच के दौरान...' और '... उप-खंड (1) में जांच या परीक्षण शुरू होने से पहले और '... उपखंड (6) में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि इस प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट की भूमिका ज्ञापन बनाने और यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि अभियुक्त को मुकदमे के शुरू होने से पहले अपने अधिकारों के बारे में पता है, जबकि जांच अभी भी चल रही है। बयान/स्वीकारोक्ति के रिकॉर्ड के नीचे दिया गया उनका ज्ञापन दस्तावेज़ की पवित्रता को बढ़ाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस तरह के बयान/स्वीकारोक्ति को रिकॉर्ड करते समय उचित सावधानी और सावधानी बरती गई थी।

29. इसी तरह, यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि धारा 169 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को आरोपी को अग्रेषित करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो उक्त अधिकारी ऐसे व्यक्ति को रिहा कर सकता है यदि हिरासत में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का निर्देश दिया जाता है, जिसे पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है; आरोपी पर मुकदमा चलाना या उसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करना। यहां भी, मजिस्ट्रेट को मुकदमे के बारे में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अधिकारी आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होने का निर्देश देता है, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का

अधिकार है, जिसमें संज्ञान लेना, मामले को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना और आरोपी पर मुकदमा चलाना शामिल है।

30. अंत में, सीआरपीसी की धारा 170 के उप-खंड (1) में प्रावधान है कि यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि धारा 169 में बताए गए अनुसार पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी अभियुक्त को हिरासत में एक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसे अधिकार प्राप्त किया गया है i) पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए, ii) आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए या iii) आरोपी को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए। **जिस उद्देश्य के लिए किसी आरोपी को चार्जशीट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, वह यह है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान ले, आरोपी पर मुकदमा चलाए या उसे सत्र न्यायालय में मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करे और न्यायिक प्रक्रिया शुरू करे।**

31. सीआरपीसी की धारा 167 के तहत जांच पूरी होने और धारा 173 सीआरपीसी के तहत इस तरह के पूरा होने की रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद, मजिस्ट्रेट का न्यायिक कार्य शुरू होता है, जहां उसे अपराध का संज्ञान लेने और मामले में आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है या मामले को सत्र न्यायाधीश द्वारा परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध करना होता है यदि मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है। आगे की सभी कार्यवाहियां जिनमें आपराधिक मामले में आगे बढ़ने के लिए न्यायिक दिमाग का उपयोग शामिल होता है, जैसे संज्ञान लेना, सत्र अदालत को मामला सौंपना, आरोपी के खिलाफ आरोप तय करना, आरोपी से पूछताछ सहित साक्ष्य लेना, सुनवाई आदि इस बिंदु से शुरू होती हैं (पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामलों में)। सीआरपीसी की धारा 173 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पक्षकारों के नामों सहित रिपोर्ट को अग्रेषित करेंगे; जानकारी की प्रकृति; उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं; क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और

यदि हां, तो किसके द्वारा; क्या ऐसे व्यक्ति/आरोपी को गिरफ्तार किया गया है; क्या ऐसे व्यक्ति/अभियुक्त को जमानत के साथ/बिना मुचलके पर रिहा किया गया है; क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेजा गया है और यदि अपराध कुछ विशिष्ट धाराओं से संबंधित है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं, तो क्या महिला की चिकित्सा जांच की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को संलग्न की गई थी, जिसे पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है।कोई भी साधारण दिमाग वाला व्यक्ति, यथोचित विवेकपूर्ण व्यक्ति को छोड़ दें, यह भी समझ सकता है कि उपरोक्त जानकारी वाली रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जाती है ताकि वह अपने न्यायिक दिमाग के आवेदन के बाद अपराध का संज्ञान ले सके और मामले में आगे बढ़ सके। धारा 173 के तहत रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है, जिसका संदर्भ धारा 190 (1) (ख) के तहत '... ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर; '.. जैसे शब्दों का प्रयोग. जैसे ही ..' का तात्पर्य है कि जांच पूरी होने के ठीक बाद, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है, जिसे अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है।हालांकि यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट रिपोर्ट का अध्ययन करेगा, लेकिन धारा 173 के प्रावधान से समान अर्थ प्राप्त करने के लिए, उप-खंड (4) को उन उदाहरणों में से एक के रूप में देखा जा सकता है जो उसी का प्रमाण है। इसमें कहा गया है कि जब भी किसी रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अग्रेषित किया गया है। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट को इस तरह के बॉन्ड या अन्य आदेश के निर्वहन का आदेश देने से पहले यह देखने के लिए रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा कि आरोपी को बॉन्ड पर रिहा किया गया था या नहीं।

32. सबसे पहले, यह समझना उचित है कि 'संज्ञान' शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है। दंड प्रक्रिया संहिता में इस शब्द के लिए कोई निश्चित परिभाषा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'संज्ञान' पर चर्चा करते हुए पारित न्यायिक निर्णयों की श्रृंखला से, यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि इसे'**मामले में आगे बढ़ने के लिए**

न्यायिक दिमाग के औपचारिक अनुप्रयोग' के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

33. इसके बाद, यह समझना तर्कसंगत होगा कि 'मामले में आगे बढ़ने के लिए न्यायिक दिमाग के औपचारिक अनुप्रयोग' का क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी शिकायत मिलने के बाद अगर मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 200 के तहत जांच शुरू करने और शिकायतकर्ता और धारा 202 सीआरपीसी के तहत उसके गवाहों की जांच करने का मन बनाता है, तो जिस क्षण वह इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय करता है, उसने संज्ञान लिया है।

34. सीआरपीसी की धारा 190 के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी पुलिस रिपोर्ट में निहित तथ्यों के आधार पर गठित किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, मजिस्ट्रेट, यदि मामले को सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य पाता है; सीआरपीसी की धारा 207 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि प्रावधान में उल्लिखित दस्तावेजों की सूची की एक प्रति आरोपी को बिना किसी देरी या जुर्माना लगाए किसी भी मामले में प्रदान की जाए, जहां पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई है। इस धारा के पहले परंतुक में कहा गया है कि प्रस्तावित व्यक्तियों के बयानों से किसी भी हिस्से को हटाने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, जिसे अभियोजन पक्ष धारा 161 (3) के तहत दर्ज किए गए गवाह के रूप में जांचना चाहता है, मजिस्ट्रेट ऐसे बयान के किसी भी हिस्से को देखने के बाद, जैसाकि ऊपर संदर्भित और उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट है और पुलिस अधिकारी द्वारा बताए गए कारणों पर विचार करने के बाद पोस्ट कर सकता है, निर्देश दें कि इस तरह के हिस्से वाली एक प्रति आरोपी को दी जाए। इस धारा के दूसरे परंतुक में यह भी कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि उपखंड (V) में दिया गया कोई दस्तावेज भारी

भरकम है, तो वह अभियुक्त को निदेश देगा और उसे आरोपी को इसकी एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए ऐसे दस्तावेज का व्यक्तिगत रूप से या अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से निरीक्षण करने की अनुमति देगा।...'. संहिता के सिद्धांत से पता चलता है कि दोनों राइडर्स यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि धारा 207 सीआरपीसी के तहत निर्धारित चरण अपराध का संज्ञान लेने के बाद ही आता है और यह विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों से बहुत स्पष्ट है, विशेष रूप से *'... इस तरह के बयान के ऐसे किसी भी हिस्से को देखने के बाद ...' और '... यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हैं...'* नतीजतन, यह व्याख्या की जा सकती है कि मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज एफआईआर को देखना होगा; सीआरपीसी की धारा 161 (3) के तहत दर्ज अभियोजन पक्ष के प्रस्तावित गवाहों के बयानों, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए कबूलनामे और बयानों की जांच करें और धारा 173 सीआरपीसी के उप-खंड (5) के तहत मजिस्ट्रेट को अग्रेषित ऐसी किसी भी अन्य सामग्री की अन्य सामग्री या प्रासंगिक निष्कर्ष का अवलोकन करें। इसके अलावा, यह कहा जा सकता है कि पुलिस रिपोर्ट की जांच और उसके बाद, मामले को सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य पाए जाने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट ने अपने दिमाग को लगाया है कि कौन सा अपराध कथित तौर पर किया गया है।

35. जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, सीआरपीसी की धारा 173 को एक सादा, सीधा पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस उप-खंड (2) (i) (क) से (ज) में तैयार की गई जानकारी वाली एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करती है और धारा 207 के अवलोकन और पूर्व-उक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट प्रावधान में उल्लिखित सभी दस्तावेजों का अध्ययन करता है। धारा 173 और 207 इस अर्थ में एक-दूसरे के अनुरूप या पारस्परिक प्रावधान हैं कि पुलिस/कोई अन्य जांच एजेंसी विशिष्ट विवरण सहित पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करती है जिसे पूर्व के तहत

संज्ञान लेने का अधिकार है और मजिस्ट्रेट अन्य दस्तावेजों के साथ उन विशिष्ट विवरणों वाली अग्रेषित पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करता है और वह रिपोर्ट देखता है। मामले में आगे बढ़ने से पहले इसका अध्ययन करें और इसकी जांच करें। रिपोर्ट पर विचार करने और पढ़ने की इस प्रक्रिया का मतलब सीआरपीसी की धारा 190 के तहत परिकल्पित संज्ञान लेना होगा। सीआरपीसी की धारा 170 के उप-खंड (2) (i) (क) से (ज) और धारा 207 सीआरपीसी के उप-खंड (i) से (V) में बताई गई जानकारी पर एक नज़र डालना "संज्ञान" शब्द के समान है।

36. यहां समझने की जरूरत यह है कि मजिस्ट्रेट को कैसे पता चलेगा कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है। यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, तो इसका मतलब है कि उसे अपना दिमाग लगाना पड़ा है, भले ही उसने पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत बयानों का अवलोकन या अध्ययन किया हो।

ख) सीआरपीसी की धारा 209: सत्र न्यायालय में मामले की प्रतिबद्धता जब अपराध विशेष रूप से उसके द्वारा सुनवाई योग्य हो।

37. इसके बाद जो होता है वह यह है कि यदि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, तो, धारा 209 सीआरपीसी के चरण तक पहुंचने तक, यह निश्चित है कि न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है, विशेष रूप से क्योंकि धारा 209 के उप-खंड (क) में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट धारा 207 या 208 के प्रावधानों का पालन करने के बाद सत्र न्यायालय में मामला कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 209 का विश्लेषण करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, इसकी सामग्री को नीचे दोहराया जाना उचित समझा जाता है:

209. सत्र न्यायालय के प्रति मामले की वचनबद्धता जब अपराध अनन्य रूप से उसके द्वारा विचारणीय हो-जब पुलिस

रिपोर्ट पर या अन्यथा स्थापित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या उसे लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह-

(क) धारा 207 या धारा 208 के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद, जैसा भी मामला हो, मामले को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना और जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अभियुक्त को तब तक हिरासत में भेजना जब तक कि ऐसी वचनबद्धता नहीं की जाती है;

(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अभियुक्त को मुकदमे के दौरान और सुनवाई के समापन तक हिरासत में भेजना;

(ग) उस न्यायालय को मामले का रिकॉर्ड और दस्तावेज और लेख, यदि कोई हों, भेजें, जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना है;

(घ) सत्र न्यायालय को मामले की प्रतिबद्धता के बारे में लोक अभियोजक को सूचित करना।

38. पूर्व-पुनरुत्पादित प्रावधान के कुछ हिस्सों को केवल आगामी पैराग्राफ में आगामी चर्चा में कुछ विशिष्ट पहलुओं को समझाने और रखने के साथ-साथ इच्छित संदर्भ में पढ़ने की सुविधा के लिए रेखांकित और लागू किया गया है।

39. i) इस प्रावधान की शुरुआत में, ***'स्थापित'*** शब्द का उपयोग किया गया है जो दर्शाता है कि मामला अदालत द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा स्थापित किया गया है। किसी मामले को स्थापित करने का सीधा सा मतलब है कि इसे आपराधिक नियमित मामले के रूप में दर्ज करना और

इसकी पहचान के लिए इसे एक विशेष संख्या सौंपना। जाहिर है, वर्तमान मामले में, ऐसा नहीं किया गया था जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिए बिना आरोपी की रिमांड की अवधि निर्धारित अवधि से आगे बढ़ा दी थी।

ii) आगे बढ़ते हुए, प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि ***'यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है',***तो, वह धारा 207 या धारा 208 सीआरपीसी के तहत सन्निहित धाराओं का पालन करने के बाद अभियुक्त को प्रतिबद्ध करेगा और उसे तब तक हिरासत में रखेगा जब तक कि ऐसी प्रतिबद्धता नहीं की जाती है या मुकदमे के समापन तक; मामले के रिकॉर्ड और दस्तावेज और लेख, जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, यदि कोई हो, सत्र न्यायालय को भेजें और सत्र न्यायालय में मामले की प्रतिबद्धता के बारे में लोक अभियोजक को सूचित करेगा।ध्यान देने योग्य हैं; मजिस्ट्रेट को यह कैसे दिखाई देगा कि कोई मामला सेशन ट्रायल योग्य है? यह तब होगा जब मजिस्ट्रेट ने ऊपर उल्लिखित तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा, इस प्रकार, शब्द "... यह मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है..." **इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि मामले की प्रक्रियात्मक यात्रा संज्ञान के बाद के चरण में प्रवेश कर चुकी है जब सीआरपीसी की धारा 209 के अनुसार रिमांड के लिए आदेश पारित किया जा रहा है।** प्रतिबद्धता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अनिवार्य है।जब मामले की फाइल और आरोपी (यदि वह हिरासत में है) सत्र न्यायालय में पहुंच गया हो और सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई की तारीख तय की गई हो, तब इसे पूरा माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मजिस्ट्रेट ने 04.07.2023 को मामले को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और यह 24.07.2023 को सत्र न्यायालय में पहुंच गया, तो जब सत्र न्यायाधीश 24.07.2023 को मामले की सुनवाई करेंगे, तो इसे पूरा माना जाएगा। सीआरपीसी की धारा 209 के उप-खंड(ख) में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट रिमांड आदेश पारित कर सकता है जो मुकदमे के दौरान और सत्र मामले

के पूरे जीवनकाल तक तब तक रहेगा जब तक कि सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी किए जाने/दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं निकल जाता। इसलिए, धारा 209 मजिस्ट्रेट को रिमांड का आदेश पारित करने का अधिकार देती है ताकि यह मुकदमे के अंत तक जारी रहे, चाहे वह एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष और इसी तरह का मामला हो।यह एक बार की रिमांड है जिसमें धारा 167 सीआरपीसी के तहत पारित रिमांड के आदेश की तुलना में अलग-अलग विशेषताएं और विशेषताएं हैं, जिसे एक बार में केवल 15 दिनों की अवधि के लिए पारित किया जा सकता है और फिर 60 या 90 दिनों (विशेष क़ानून के अनुसार 180 दिन) की निश्चित समय अवधि तक 15 दिनों के लगातार ब्रैकेट के लिए बढ़ाया जा सकता है।कभी-कभी, धारा 209 के उप-खंड (क) को समझना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह एक कॉम्पैक्ट वाक्य में कई पहलुओं को शामिल करता है, इस प्रकार, इसे स्पष्ट करने और इसे स्पष्ट तरीके से निर्धारित करने के लिए, इसे वर्तमान मामले के लिए निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है: "... वह धारा 207 या धारा 208 के प्रावधानों का पालन करने के बाद, जैसा भी मामला हो, मामले को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और आरोपी को तब तक हिरासत में भेजेगा जब तक कि ऐसी प्रतिबद्धता नहीं की जाती है; इस प्रकार, और उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करते हुए, मजिस्ट्रेट अपने दिमाग का उपयोग करता है और उसे पता चलता है कि क्या मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, जिसका अर्थ है कि परिणामस्वरूप, वह संज्ञान लेता है और निर्णय लेता है कि क्या उसे प्रतिबद्धता के लिए आगे बढ़ना है और धारा 209 के प्रावधान की ओर बढ़ना है।

40. जैसा कि पहले के पैराग्राफ में बताया गया है, सीआरपीसी की धारा 209 संज्ञान के बाद के चरण में रिमांड का आदेश पारित करने की कल्पना करती है, लेकिन यह तत्काल मामले में काम नहीं कर सकती क्योंकि न तो इस मामले में संज्ञान लिया गया था और न ही मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने के लिए कोई और कदम उठाया गया था। धारा 209

के प्रावधान पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि अभियुक्त को रिमांड पर भेजने का आदेश केवल मुकदमे के चरण तक और साथ ही मुकदमे के समापन तक पारित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संज्ञान लेने, प्रतिबद्धता की प्रक्रिया की ओर बढ़ने और स्वाभाविक रूप से, मामले को एक नियमित मामले के रूप में स्थापित करने के बाद किया जा सकता है।

41. दिनांक 27.03.2023 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि विद्वान मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया कि धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध गंभीर प्रकृति का है और सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना है, लेकिन कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए इस संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। जहां तक डिफ़ॉल्ट जमानत का प्रश्न था, विद्वान मजिस्ट्रेट ने तर्क दिया है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब जांच एजेंसी द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था, उसी दिन, सीआरपीसी की धारा 190 के तहत एक आवेदन भी शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया था।इसके बाद, उन्होंने आगे तर्क दिया है कि चूंकि सीआरपीसी की धारा 190 के तहत दायर आवेदन उत्तर दायर करने के अभाव में लंबित था और अधिवक्ता हड़ताल पर थे, इसलिए मामले में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, ऐसा कुछ भी नहीं था जो विद्वान मजिस्ट्रेट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार मामले में आगे बढ़ने से रोक रहा था, फिर भी किसी भी तरह से कोई न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी और रिमांड के विस्तार का आदेश मामले की संस्था या संज्ञान के किसी औपचारिक आदेश के बिना पारित किया गया था। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, इस मामले की दी गई परिस्थितियों में 90 दिनों के बाद पारित रिमांड के आदेश में धारा 209 सीआरपीसी का अधिकार या मंजूरी नहीं है और इसे किसी भी तरह से धारा 209 सीआरपीसी के दायरे में नहीं लाया जा

सकता है।

ग) धारा 309 सीआरपीसी: कार्यवाही को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति।

42. सीआरपीसी की धारा 309 के उप-खंड (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदालत आरोपी को रिमांड पर भेजने के लिए वारंट जारी कर सकती है यदि वह किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद या मुकदमे के शुरू होने के बाद हिरासत में है और इस बात पर फिर से जोर दिया जाता है कि यह प्रावधान केवल पोस्ट-संज्ञान चरण में संचालित होता है जो स्पष्ट रूप से मामले में नहीं पहुंचा है। संज्ञान लेना तो दूर, मामले को नियमित मामले के रूप में भी दर्ज नहीं किया गया है। उपरोक्त चर्चा का सारांश यह है कि इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता में 'संज्ञान' शब्द को ट्रैक किया है, जो एक प्रावधान से दूसरे प्रावधान में स्थानांतरित हो रहा है जैसे कि पानी पर पत्थर को छोड़ना ताकि इसे स्पष्ट अर्थ दिया जा सके। संज्ञान की परिभाषा किसी एक प्रावधान से अलग नहीं है, बल्कि इसे संहिता को पूरी तरह से पढ़कर समझा जाना चाहिए और यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया था और इस प्रकार, तत्काल मामले में सीआरपीसी की धारा 309 के तहत रिमांड का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

43. जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167, 209 और 309 में परिकल्पित है और ऊपर दिए गए इस न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों की घोषणा के अनुसार, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में 90 दिन बीतने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड के विस्तार का आदेश कानून में गलत था या दूसरे शब्दों में, अपनाई गई प्रक्रिया सांविधिक प्रावधानों के पूर्ण अनुरूप नहीं थी।

44. दंड प्रक्रिया संहिता की योजना ऐसी है कि एक बार जांच चरण पूरा हो जाने के बाद, न्यायालय अगले चरण में आगे बढ़ता है, जो संज्ञान ले रहा है और फिर मुकदमे के अगले चरणों में आगे बढ़ता है। जमानत पर रिहा

नहीं होने पर आरोपी को किसी न किसी न्यायालय की हिरासत में रहना पड़ता है।जांच की अवधि के दौरान, आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है जिसके समक्ष उसे पहली बार प्रस्तुत किया जाता है। उस चरण के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत, मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को **पुलिस हिरासत और/या न्यायिक हिरासत** दोनों में एक बार में 15 दिनों के लिए, 10 वर्ष तक के कारावास के लिए दंडनीय अपराधों के मामलों में अधिकतम 60 दिनों तक और 90 दिनों तक की सजा के लिए अभियुक्त को हिरासत में भेजने का अधिकार निहित है, जहां अपराध 10 वर्ष और उससे अधिक या यहां तक कि मौत की सजा के लिए दंडनीय हैं।यदि कोई जांच प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर करने में विफल रहता है, तो आरोपी वैधानिक जमानत पर रिहा होने का पात्र है। दूसरी ओर, जब अभियुक्त अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने तक मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है, जब उक्त न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के संदर्भ में मुकदमे के दौरान रिमांड के प्रयोजनों के लिए अभियुक्त की हिरासत लेता है। दो चरण अलग-अलग हैं, लेकिन एक दूसरे का अनुसरण करता है ताकि न्यायालय के साथ आरोपी की हिरासत की निरंतरता बनी रहे।

45. यह समझा जा सकता है कि जांच की अवधि के दौरान, अभियुक्त उस मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है जिसे उसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था और ऐसे मजिस्ट्रेट को आरोपी द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा की अवधि के अनुसार 60 दिनों और 90 दिनों की अवधि के दौरान 15 दिनों की अवधि के लिए आरोपी को न्यायिक/पुलिस हिरासत में भेजने का अधिकार है। यदि 60 या 90 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो आरोपी वैधानिक जमानत पर रिहा होने के लिए उत्तरदायी है।लेकिन, यदि आरोप-पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किया जाता है, तो, जैसाकि ***सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य*** (2013) 3 एससीसी 77 में प्रकाशित में बताया गया है, आरोपी

तब तक मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है जब तक कि उपयुक्त अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है और ऐसी अदालत सीआरपीसी की धारा 309 के उद्देश्य से आरोपी की रिमांड का आदेश पारित करती है।यदि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जाती है, तो सीआरपीसी की धारा 209 के तहत आदेश पारित किया जाएगा। ***भीकमचंद*** (सुप्रा.) में यह भी कहा गया है कि कानून द्वारा रिमांड का आदेश पारित करने वाली न्यायालय को शक्ति दिए बिना रिमांड का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, हालांकि जब जांच का चरण समाप्त हो जाता है और संज्ञान लेने और परीक्षण के संचालन के साथ आगे बढ़ने का अगला चरण शुरू होता है, तो प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने के लिए, आरोपी की हिरासत को मजिस्ट्रेट के पास तब तक रखा जा सकता है जब तक कि संज्ञान नहीं लिया जाता है और धारा 209 या 309 सीआरपीसी के तहत रिमांड का आदेश पारित किया जा सकता है, लेकिन इसे कानून की मंजूरी और शरण नहीं मिलती है। आरोपी को हिरासत में भेजते समय और संज्ञान लेने को टालते समय बिना किसी वैध कारण के ऐसा नहीं किया जा सकता है। आरोप-पत्र दायर करने और मामले का संज्ञान लेने के बीच की अवधि के दौरान अभियुक्त की इस तरह की हिरासत को एक नियमित प्रथा नहीं माना जा सकता है क्योंकि न केवल इसकी कोई मंजूरी या आधार नहीं है बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित अधिकारों की छतरी के तहत गारंटीकृत अभियुक्त के अधिकारों के खिलाफ भी जाता है।

46. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और आपराधिक अधिनिर्णय के लिए स्थापित प्रक्रियात्मक कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता है जो ऐसी किसी रिमांड को निर्धारित नहीं करता है या आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून द्वारा ऐसी किसी रिमांड की परिकल्पना नहीं की गई है।

47. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आरोपी को संज्ञान लेने से पहले थोड़े समय के लिए हिरासत में रहना पड़ता है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि क़ानून, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा स्वीकृत किए बिना रिमांड नहीं हो सकती है। कानून के शासन और राजा/तानाशाह के शासन के बीच मूल अंतर यह है कि उत्तरार्द्ध की अवधारणा में, राजा को व्यक्तिगत रूप से सही माना जाता है क्योंकि राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता है और पतन से प्रतिरक्षा है; वह कुछ भी कर सकता है जैसा वह उचित समझता है; यह उसकी इच्छा, सनक और पसंद के अनुसार या व्यक्तिगत धारणा के अनुसार हो सकता है।इसके लिए नियम, संस्था, आम सहमति, कार्य या "सामान्य इच्छा" की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। भारत ने कानून के शासन/कानून के सिद्धांत की अवधारणा को अपनाया और इस अवधारणा के अनुसार, एक न्यायिक/सार्वजनिक अधिकारी के प्रत्येक कार्य के लिए कानून की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कानून के समर्थन से रहित या उससे किसी भी विचलन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून में निश्चित चरण होते हैं और क़ानून ने रिमांड का आदेश पारित करने के लिए तीन अलग-अलग अपेक्षित चरणों में विकल्प प्रदान किए हैं, इसलिए, रिमांड का एक आदेश जो आदर्श रूप से बाद के चरण में पारित किया जाना है, उस चरण से पहले की अवधि के लिए वैध नहीं ठहराया जा सकता है।वर्तमान मामले में जो परिदृश्य हुआ वह एक ऐसी अवधि से संबंधित है जो दो चरणों के बीच निलंबित है, उनमें से किसी के साथ प्रतिच्छेद नहीं करता है और इस प्रकार, इस तथ्य के बारे में सतर्क रहना और आरोपी को हिरासत में नहीं लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिसे कानून का कोई अनुमोदन नहीं है। संज्ञान न लेने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए बहाने इतने सम्मोहक नहीं हैं कि आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून के दुरुपयोग की अनुमति दी जा सके या समायोजित किया जा सके। यदि किसी ऐसे

अतिरिक्त आरोपी को आरोपित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके खिलाफ आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया था, तब भी, मजिस्ट्रेट के लिए अपराध का संज्ञान लेने और फिर एक अतिरिक्त आरोपी को आरोपित करने के आवेदन पर सुनवाई करने के लिए कोई विधिक रोक नहीं थी।यह स्पष्ट किया जाता है कि अदालत अपराध का संज्ञान लेती है, न कि अपराधी का। उन्हें दो मौकों पर संज्ञान लेने से डरना नहीं चाहिए था-एक कुछ आरोपियों के लिए और फिर, शेष अभियुक्तों के लिए; अपराध का संज्ञान लेने के बाद, यदि निचली अदालतआगे बढ़ता है और किसी भी अतिरिक्त आरोपी को आरोपित करने या जोड़ने के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो वह उस पर विचार कर सकता है और यदि उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई जाती है जिसके खिलाफ आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है, तो अतिरिक्त आरोपी को जोड़ने का आदेश पारित किया जा सकता है।विभिन्न अवसरों पर दिए गए स्थगनों में कटौती की जा सकती थी और संज्ञान लेते हुए एक आदेश आसानी से पारित किया जा सकता था क्योंकि वर्तमान ऐसा मामला भी नहीं है जहां किसी भी प्रकार की अभियोजन मंजूरी की आवश्यकता थी, जैसाकि इस विषय पर पारित कई उदाहरणों में हुआ है। इसके अलावा, संहिता सीआरपीसी की धारा 190 (1) (क)/190 (1) (ख) के तहत संज्ञान लेने को उचित महत्व देती है क्योंकि धारा 460 सीआरपीसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि इन खंडों के तहत संज्ञान अच्छी नीयत से लिया गया है, हालांकि मजिस्ट्रेट को ऐसा करने का अधिकार नहीं था, तो उसके द्वारा की गई कार्यवाही को धारा 460 सीआरपीसी के अनुसार अपास्त नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 460 के तहत दिया गया यह संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि यदि मजिस्ट्रेट ने गलती से लेकिन अच्छे इरादे से अपराध का संज्ञान लिया है, तो इस तरह से की गई कार्यवाही को अपास्त नहीं किया जाएगा।

48. इस प्रकार, किसी भी वैधानिक शर्त के रूप में कोई बाधा नहीं थी जो दोषी

अधिकारी को आगे बढ़ने से रोक सकती थी और प्रक्रिया को आपराधिक प्रक्रियात्मक संहिता में दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी रखा जाना चाहिए था, इस प्रकार, मामले का संज्ञान लेने या कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ने में देरी करने का कोई अवसर नहीं था। वर्तमान मामले में निरोध को मंजूरी नहीं दी गई है और कानून की मंजूरी नहीं है; कानून में किसी अंतर्निहित आधार के बिना किसी व्यक्ति की इच्छा और समझ पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

49. चूंकि संहिता में कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो किसी आरोपी व्यक्ति को रिमांड देने /बढ़ाने में सक्षम बनाता है, इसलिए आरोप-पत्र दायर करने के बाद और संज्ञान लेने से पहले विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्तागण की रिमांड का निरंतर विस्तार कानून द्वारा अनुचित और अपुष्ट था, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा सही प्रक्रिया सीखने के प्रयास के प्रकाश में और वर्तमान मामले के अपने आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रक्रियात्मक कानून भी इस पहलू पर स्पष्ट नहीं था कि क्या किया जाना चाहिए या किस प्रावधान के तहत अभियुक्त को आगे की विस्तारित अवधि के लिए रिमांड पर रखा जाना चाहिए या आरोप-पत्र दायर करने के बाद मध्ययुगीन काल में क्या किया जाना चाहिए और मामले की स्थापना से पहले/इस न्यायालय को लगता है कि अधिकारी से क्षतिपूर्ति मांगने या लोगों के हितों के खिलाफ आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

50. हालांकि यह सच है कि बाद की विधिक कार्रवाई पहले के अवसर पर पारित लापरवाह आदेश को वैध नहीं बनाती है, हालांकि, फिलहाल, मामला दर्ज किया गया है और संज्ञान लिया गया है, इसलिए अब पुल के नीचे पानी है।

51. तदनुसार, तत्काल पुनरीक्षण याचिका का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

52. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

53. यह न्यायालय जांच एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र दायर करने के बाद और मामले की स्थापना/संज्ञान लेने या मामले की प्रगति से पहले हिरासत की वैधता के प्रश्न के संबंध में आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून में मौजूद गुहा से अवगत है, हालांकि, चूंकि इस मामले में मुकदमा अगले चरणों की ओर बढ़ गया है, इस स्तर पर इस मुद्दे पर निर्णय लेना उचित नहीं समझा गया है।

54. यह देखते हुए कि त्रुटिपूर्ण आदेश नहीं दिया गया है या त्रुटि जानबूझकर नहीं की गई है, बल्कि न्यायिक अधिकारी प्रामाणिक और कानून की गलत धारणा के तहत कार्य कर रहा था, और यह अच्छी नीयत से की गई कार्रवाई थी, इसलिए, यह न्यायालय उसके खिलाफ कार्यवाही करना उचित नहीं समझता है, हालांकि, उसे कानून के प्रति जागरूक होने और परीक्षण करते समय सावधान रहने के लिए संवेदनशील बनाया जाता है ताकि अधिकारों को किसी भी पक्षकार में पूर्वाग्रह न हो। हालांकि, निर्णय के पिछले पैराग्राफ में चर्चा किए गए विधिक मुद्दे पर स्पष्टता की कमी है, फिर भी वह भविष्य में खुद को सतर्क रखेंगे ताकि उनके सामने राहत की गुहार लगाने वाले पक्षों के अधिकारों को कुचलने से रोका जा सके।

(फरजंद अली), न्यायमूर्ति

148-/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।